भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2956

06 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

जन पोषण केंद्र पायलट परियोजना

2956. श्री पी. पी. चौधरी:

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:

श्री प्रवीण पटेल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जन पोषण केंद्र पायलट परियोजना के माध्यम से सरकार द्वारा किन चुनौतियों का समाधान किया गया है;

(ख) इस आधुनिकीकरण पहल का पायलट अध्ययन किन राज्यों में शुरू किया गया है और उक्त परियोजना के अंतर्गत देश में, विशेष रूप से पाली संसदीय क्षेत्र सहित राजस्थान में, खोली गई उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) की संख्या क्या है; और

(ग) उक्त आधुनिकीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने उचित दर दुकानों (एफपीएस) को जन पोषण केंद्र (जेपीके) में बदलने के लिए एक प्रायोगिक अध्ययन शुरू किया है। भारत सरकार ने यह प्रायोगिक कार्यक्रम एफपीएस डीलरों की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने के साथ-साथ लाभार्थियों के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किया है।

इसके अलावा, उचित दर दुकान (एफपीएस) डीलरों के सामने आने वाली कौशल विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए, विभाग ने राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के माध्यम से क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिसमें विशेष रूप से डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और बाजार में बदलावों के अनुकूल होने और नए व्यापार अवसरों का पता लगाने के लिए आवश्यक उद्यमशीलता कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

वर्तमान में, इस प्रायोगिक अध्ययन के तहत, 90 एफपीएस को, अर्थात 4 शहरों नामतः हैदराबाद, गाजियाबाद, जयपुर, अहमदाबाद से 15-15 और इंदौर से 30 को जेपीके में परिवर्तित किया गया है।

राज्यों को, इस पहल में अपनी इच्छानुसार किसी भी संख्या में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

*****